भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 915

उत्तर देने की तारीख : 19.09.2020

बंद होने के कगार पर एमएसएमई

915. श्रीमती फूलो देवी नेतम:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वित्तीय वर्ष 2014-15 और 2019-20 के बीच देश में कितने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) पंजीकृत किए गए;

(ख) वित्तीय वर्ष 2014-15 और 2019-20 के बीच कितने एमएसएमई बंद हो गए और इसके क्या कारण रहे हैं;

(ग) मार्च, 2020 से अगस्त, 2020 के बीच आर्थिक संकट के कारण कितने एमएसएमई बंद हुए हैं; और

(घ) कोविड-19 वैश्विक महामारी की शुरुआत के बाद एमएसएमई की सहायता करने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री प्रताप चन्द्र "kM›+h)

(क) : व्यापार करने की सुगमता के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का ऑनलाइन पंजीकरण सितम्बर, 2015 में शुरु हुआ था। तब से ऑनलाइन फाइलिंग से संबंधित वर्ष-वार आंकड़े उद्योग आधार ज्ञापन (यूएएम) पोर्टल पर उपलब्ध हैं। इसके अनुसार, वित्त वर्ष 2015-16 और 2019-20 के दौरान देशभर में पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की संख्या निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	वित्त वर्ष	सूक्ष्म	लघु	मध्यम	कुल
1	2019-20	2248848	302169	11241	2562258
2	2018-19	1868033	242244	9465	2119742
3	2017-18	1342985	167183	6733	1516901
4	2016-17	2138627	217405	8764	2364796
5	2015-16	420691	71116	2691	494498
	कुल:-	8019184	1000117	38894	9058195

(ख) : ऐसा कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है।

(ग) : ऐसा कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है।

(घ) : हाल ही में कोविड-19 के प्रसार के उपरांत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत देशभर में विशेषकर कोविड-19 महामारी से प्रभावित क्षेत्रों में एमएसएमई क्षेत्र को सहयोग प्रदान करने के लिए कई पहलें की हैं। उनमें से कुछ निम्नानुसार हैं:-

i. एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ रुपए का अधीनस्थ ऋण।
ii. एमएसएमई सहित व्यापार के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का कोलेट्रल मुक्त ऑटोमेटिक ऋण।
iii. एमएसएमई निधियों की निधि के जरिए 50,000 करोड़ रुपए का इक्विटी समावेशन।
iv. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के वर्गीकरण के लिए नया संशोधित मानदंड।
v. व्यापार करने की सुगमता हेतु 'उद्यम पंजीकरण' के जरिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का नया पंजीकरण।
vi. 200 करोड़ रुपए तक की खरीद के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं होगी, इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को सहायता मिलेगी।

माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 01.06.2020 को एक ऑनलाइन पोर्टल ''चैम्पियन'' का शुभारंभ किया गया है। इस पोर्टल में एमएसएमई की शिकायतों के निवारण और हैंडहोल्डिंग सहित ई-शासन के कई पहलुओं को शामिल किया गया है। पोर्टल के माध्यम से 13.09.2020 तक 19,224 शिकायतों का निवारण किया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने भी एमएसएमई के वित्तीय दबाव को कम करने के लिए कई उपायों की घोषणा की है।

******